RAJYA SABHA

Thursday, the 17th *May,* 2007/27 *Vaisakha,* 1929 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Questions.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार-टावर

*601. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार टॉवर संस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्य के लिए कितने गांवों के चयन की संभावना है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित ऐसे टावर अक्सर खराब ही रहते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों में संस्थापित उक्त टॉवरों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ शकील अहमद): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां कोई मौजूदा स्थिर (फिक्स्ड) वायरलेस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, स्थिर (फिक्स्ड)/मोबाइल, टर्मिनलों का उपयोग करके वायरलेस इन लोकल लूप जैसी अन्य वायरलेस अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थलों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कुल 2,12,304 गांवों को कवर किए जाने और 5 वर्षों की अवधि में इसके लिए 587.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाएं संस्थापित की गई हैं, आमतौर पर संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। तथापि, कुछ स्थानों पर अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण उक्त सेवा के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा संस्थापित टावरों के राज्य वार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा संस्थापित टावरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य	जीएसएम और डब्ल्यूएलएल के लिए 2005-06 के दौरान संस्थापित टावर (बीटीएस)			जीएसएम और डब्ल्यूएलएल के लिए 2006-07 के दौरान संस्थापित टावर (बीटीएस)		
		जीएसएम	डब्ल्यूएलएल	कुल	जीएसएम	डब्ल्यूएलएल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	456	02	458	486	159	645
2	उत्तरांचल	131	26	157	53	33	86
3	पंजाब	365	49	414	324	12	336
4	राजस्थान	281	59	340	439	142	581
5	हिमाचल प्रदेश	95	37	132	198	32	230
6	हरियाणा	409	0	409	143	48	191
7	जम्मू व कश्मीर	82	0	82	52	39	91
8	उड़ीसा	90	0	90	241	81	322
9	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	269	26	295	113	71	184

1	2	3	4	5	6	7	8
10	बिहार	160	0	160	91	95	186
11	झारखंड	77	0	77	49	32	81
12	अंडमान व निकोबार	07	0	07	13	0	13
13	असम को छोड़कर पूर्वोत्तर	57	12	69	39	75	114
14	असम	100	0	100	104	113	217
15	आंध्र प्रदेश	270	245	515	323	18	341
16	कर्नाटक	284	135	419	111	41	152
17	केरल	310	279	589	322	89	411
18	तमिलनाडु	324	209	533	384	43	427
19	छत्तीसगढ़	79	04	83	28	16	44
20	गुजरात	75	30	105	623	63	686
21	मध्य प्रदेश	24	25	49	213	53	266
22	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	300	113	413	551	218	769
	कुल जोड़:	4245	1251	5496	4900	1473	6373

Telecommunication towers in rural areas

†* 601. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are contemplating on installing telecommunication towers in rural areas of the country;

(b) if so, the details thereof;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) the number of villages likely to be selected for the said purpose and the amount likely to be spent on the same;

(d) whether it is also a fact that said towers installed at present in rural areas generally remain out of order; and

(e) if not, the details of said towers installed during the last two years, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DR. SHAKEEL AHMAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) A scheme has been launched by the Government to provide support for setting up and managing 7871 number of infrastructure sites spread over 500 districts in the country for provision of mobile services including other Wireless Access Services like Wireless in Local Loop (WLL) using Fixed/Mobile terminals in the specified rural and remote areas, where there is no existing fixed wireless or mobile coverage. A total number of 2,12,304 villages are likely to be covered and a sum Rs. 587.88 crore is likely to be disbursed over a period of 5 years under this scheme.

(d) and (e) No, Sir. Mobile services of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), wherever deployed in rural areas in the country are working satisfactory, in general. However, inadequate power supply is affecting performance of the said service at some places. A statement indicating State-wise details of towers installed by BSNL during the last two years is given in the Statement-I.

Statement-I

State-wise details of towers in rural areas installed by BSNL during last two years

Sl. No.	State	Tower(BTS) Installed during 2005-06 for GSM & WLL			Towers(BTS) Installed during 2006-07 for GSM & WLL		
		GSM	WLL	Total	GSM	WLL	Total
1.	Uttar Pradesh	456	02	458	486	159	645
2.	Uttaranchal	131	26	157	53	33	86
3.	Punjab	365	49	414	324	12	336
4.	Rajasthan	281	59	340	439	142	581
5.	Himachal Pradesh	95	37	132	198	32	230
6.	Haryana	409	0	409	143	48	191
7.	Jammu and Kashmir	82	0	82	52	39	91
8.	Orissa	90	0	90	241	81	322
9.	West Bengal (including Sikkim)	269	26	295	113	71	184
10.	Bihar	160	0	160	91	95	186
11.	Jharkhand	77	0	77	49	32	81
12.	Andaman & Nicobar	07	0	07	13	0	13
13.	North East except Assam	57	12	69	39	75	114
14.	Assam	100	0	100	104	113	217
15.	Andhra Pradesh	270	245	515	323	18	341
16.	Karnataka	284	135	419	111	41	152
17.	Kerala	310	279	589	322	89	411
18.	Tamil Nadu	324	209	533	384	43	427
19.	Chhattisgarh	79	04	83	28	16	44
20.	Gujarat	75	30	105	623	63	686
21.	Madhya Pradesh	24	25	49	213	53	266
22.	Maharashtra (including Goa)	300	113	413	551	218	769
	TOTAL:	4,245	1,251	5,496	4,900	1,473	6,373

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें ''ख'' और ''ग'' भाग में उन्होंने कहा है कि भारत संचार निगम की मोबाइल सेवाएं संस्थापित की गई हैं और वे आमतौर पर संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं, परन्तु विद्युत के अभाव में कई जगह उन पर असर हो रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि इस बात की वे जांच करें कि कई जगह नहीं, देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें खराब रहती हैं, कारण कुछ भी हो और उसका असर सेवाओं पर पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चाहे बिजली के कारण या अन्य किसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों की टेलीफोन सेवाओं में जो खराबी आती है, इसको रोकने के लिए सरकार कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है?

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, बिजली की बात हमने अपने उत्तर में की है। आप और हम सभी जानते हैं कि बिजली देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इस देश के देहाती इलाकों में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सारी जिम्मेदारी आप राज्य सरकारों पर डालेंगे?

डा॰ शकील अहमद: इस देश के देहाती इलाकों में बिजली की जो स्थिति है, वह हमसे और आपसे छिपी नहीं है। हम अपने एक्सचेंज में जनरेटर provide करते हैं, एक एक्सचेंज में हम दो बड़े जनरेटर्स देते हैं। अगर बिजली दो घंटे, चार घंटे गई, तो जनरेटर काम में आ सकता है, यहां तो 24-24 घंटे, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे तक बिजली गायब रहती है, उसके बाद भी हमने प्रयास किया है कि हमारा देश तरक्की करे और हम देहातों में टेलीफोन की अच्छी सुविधाएं दें और हमारे क्वालिटी का जो बेंचमार्क है, यह TRAI regulate करती है और TRAI ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहीं-कहीं हमारी कमियां भी दर्शाई हैं, कहीं हमको सबसे अच्छा कहा है, कहीं-कहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी अच्छा कहा है, लेकिन landline के मामले में 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा BSNL का ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक नयी प्रवृत्ति BSNL के बारे में पूरे देश में देखने में आई है कि vested interest यानी निहित स्वार्थ के लोग BSNL का केबल जान-बूझकर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कटवा रहे हैं। Law and order भारत सरकार के हाथ में नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, Law and order की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं बिहार से आता हूं, मैं अपने हाथ से 203 FIR की copies जो हमारे पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दी हैं, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह BSNL जनता की कंपनी है, अवाम के पैसे की कंपनी है, जो vested interest के लोग भाड़े के आदमी रखकर इसके केबल कटवा रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में BSNL की मदद की आवश्यकता है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने तार चोरी होने की बहुत गंभीर बात कही है और अगर यह बात सही है, तो केवल प्रांत सरकारों पर इसे छोड़कर आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपके विभाग को भी यह कानूनी अधिकार है कि आप कार्यवाही करें। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पावर की handling की क्षमता का अंदाज़ लगाकर क्या कोई योजना सरकार तैयार कर रही है, यह इसका पहला भाग है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप टावर खड़ा करने के लिए जो जमीन लेते हैं, उसके लिए या तो आप किसान को किराया देते हैं या उससे कीमत पर लेते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि देश भर में ऐसी जमीनें जो टावर खड़ा करने के लिए किसानों से ली जाती हैं, चाहे किराए पर, चाहे कीमत पर, उसकी कोई एक सम्यक नीति जिससे देश भर में उनको समान रूप से रेट मिलें या किराया मिले, इस बारे में क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है, यदि नहीं बनाई है तो कब तक बनाने जा रही है?

डा॰ शकील अंहमद: सभापति महोदय, निश्चित रूप से उसकी एक निर्धारित नीति है। अगर हम फैसला लेते हैं कि अमुक जगह पर हम अपना टावर खड़ा करेंगे या even लैंड लाइन का एक्सचेंज बनाएंगे, तो उसके लिए अखबारों में निविदा दी जाती है, लोगों से निविदा आमंत्रित की जाती है और निविदा आमंत्रित करने के बाद जो lowest निविदा होती है, जो सरकार की प्रक्रिया है, किस जगह पर है, approach कैसा है, लोगों को वहां जाने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी...(व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: ऐसा सब जगह नहीं होता।

डा॰ शकील अहमद: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह तय करते हैं। अगर माननीय सदस्य को सूचना है कि कहीं नियमों की अनदेखी हुई है, उल्लंघन हुआ है, तो हमको सूचित करें। हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपना जवाब देते वक्त एक बड़ी सीरियस बात उजागर की कि किसी और प्लेयर के, किसी और जीएसएम प्लेयर के हक में या टेलीफोन ऑपरेटर के हक में उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी केबल काटी जा रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने तो FIR file की, क्या आपने investigation की कि कौन-सी कम्पनियां यह करा रही हैं, क्या उनके बारे में कुछ पता लगा? मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जेनरेटर एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा के लिए है, ऐसी बात नहीं है। आप तो विद्वान हैं, खुद डाक्टर हैं, जेनरेटर 24 घंटा चलता है और दूर की बात तो छोड़िए, यहीं बगल में सैनिक फार्म में जो जेनरेटर से ही 24 घंटे पूरी पॉवर सप्लाई होती है। आपके टावर में जो

जेनरेटर है, जो भी वेंडर है, जो टावर लगाता है, जो वहां सप्लाई करता है, वहां 24 घंटा जेनरेटर चला कर सप्लाई क्यों नहीं होती, वैसा जेनरेटर क्यों नहीं लगता, जो 24 घंटा पॉवर सप्लाई करे? जो आपके competitors हैं, उनके टावर को भी तो बिजली नहीं मिल रही है, किन्तु वह 24 घंटा चल रहा है। क्या आपने कभी इसका आकलन किया है?

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, माननीय सदस्य के सवाल का जो पहला भाग है, माननीय सदस्य भी उसी राज्य से आते हैं, जिस राज्य से मैं आता हूं, बिहार से और मैंने कहा कि खुद उनके बिहार में हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी FIR lodge करते हैं। उसकी जांच करना, उस पर कार्रवाई करना, यह स्थानीय सरकारों का काम है। मैंने इसी सदन में कहा कि मैंने आज से 6 महीने पहले 203 FIRs अपने हाथ से ले जा कर मुख्यमंत्री, बिहार के हाथ में दी है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह तो आपने कह दिया।

डा॰ शकील अहमद: यह मैंने कहा है। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है, तो यह जेनरेटर के ही कारण है कि हमारी सुविधाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, जवाब नहीं आ रहा है...(**व्यवधान**)... इन्होंने कहा कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है...(**व्यवधान**)...

डा॰ शकील अहमद: मेरी पूरी बात सुनिए न...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: तो कौन-सी कम्पनी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, वे उसका नाम बताएं...(**व्यवधान**)...

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, हमारे टेलीकाम कम्पनी जासूसी संस्था नहीं है। कौन तार काट रहा है, यह पता करना स्थानीय प्रशासन का काम है, यह पता लगाने की जिम्मेदारी उनकी है ...(**व्यवधान**)... मैं किसी का नाम नहीं लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि निहित स्वार्थ के लोग vested interest के लोग अपने फायदे के लिए हमारा केबल कटवा रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे हमारी मदद करें...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, अगर केबल लेड या कॉपर की होती, तो उसकी resale value है...(**व्यवधान**)... इस optical fibre cable की resale value नहीं है, तो इसको क्यों काटेगा...(**व्यवधान**)...

डा॰ शकील अहमद: जहां तक जेनरेटर का सवाल है, इसी जेनरेटर के बारे में हमने कहा है कि सामान्य तौर पर हमारी...(**व्यवधान**)... आप डिबेट करिएगा या आप answer सुनिएगा...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप गलत जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)...आप दिग्भ्रांत कर रहे हैं...(व्यवधान)...

डा॰ शकील अहमद: आप answer सुनिए, आप तो डिबेट कर रहे हैं...(व्यवधान)... आपने क्वैश्चन किया है, तो आप answer सुनिए आपने डिबेट शुरू कर दी। This is not a debate. This is Question-Answer session...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Certainly every answer generates a debate. It attracts a debate. ...*(Interruptions)*... If you mislead the House, it will attract a debate. ...*(Interruptions)*...

डा॰ शकील अहमद: आप बिना जवाब सुने बीच में interrupt कर रहे हैं। सभापति महोदय, मंत्री को भी आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मेरी सुन लीजिए। आपने जवाब दिया है कि लाभ-हानि के लिए connection काटे जाते हैं, ये उसका detail चाहते हैं।

डा॰ शकील अहमद: किस मामले में।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मंत्री महोदय बेवजह क्रोधित हो रहे हैं। वे तो केवल यह पूछ रहे हैं कि आपने FIR किसके खिलाफ दर्ज कराई, बस इतना बता दीजिए।

डा॰ शकील अहमद: एक तो जो पकड़ा गया, उसके खिलाफ ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: तो आदमी के नाम दे दीजिए न।

डा॰ शकील अहमद: और कुछ FIR unknown लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई, क्योंकि वे रात में केबल काट कर भाग जाते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: तो आप नाम बता दीजिए न! ...(व्यवधान)...

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, 5 दिन पहले पटना में वहाँ के होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और जो शासन के मुख्य लोग हैं, उनको हमने WLL provide किया। उनके लिए जो लाइन जाती है, वह केबल भी काट दिया गया ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सवाल बहुत सीधा है कि किस कम्पनी को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल इतना बता दीजिए...(व्यवधान)...

डा॰ शकील अहमद: माननीय सदस्या, हमारी कंपनी बी॰एस॰एन॰एल॰ है और किसी जगह पर आदमी पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ हम ने By name एफ॰आई॰आर॰ फाइल की है, लेकिन

ज्यादातर जगहों पर लोग रात में छुपकर काट देते हैं। पहले उसे काटकर, चोरी कर के ले जाते थे. अब काटकर वहीं छोड़ देते हैं। इस से लगता है कि यह कार्य उन्होंने चोरी के उद्देश्य से नहीं किया है बल्कि सिर्फ हम को डिस्टर्ब करने के लिए किया है। तो कुछ known लोगों के खिलाफ और कुछ unknown लोगों के खिलाफ देशभर में एफ॰आई॰आर॰ फाइल की गयी हैं। अब यह बताना कि यह किस कंपनी ने किया है और ये कौन लोग हैं, यह कार्य राज्य सरकार करेगी। यह हम कैसे कर सकते हैं?

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने वर्ष 2006-07 में गुजरात में बी॰एस॰एन॰एल॰ के सब से ज्यादा 623 टावर्स लगाए हैं। मोदी जी के गुजरात पर इन की बड़ी नजर-ए-करम रही और इन्होंने वहां सब से ज्यादा 623 टावर्स लगवाए, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां कि आबादी सब से ज्यादा है, जहां का क्षेत्रफल सब से ज्यादा है, जहां गरीबी सब से ज्यादा है और देहाती इलाके ज्यादा हैं, वहां पर 486 टावर्स लगाए हैं। मैं इन से जानना चाहता हूं कि गुजरात को इतना preference देने और यू॰पी॰ को पीछे रखने का क्या कारण है?

†**شری شاہد صدیقی** : سر، میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ورش 2006-07 میں گجرات میں بی ایس این ایل کے سب سے زیادہ 623 ٹاورس لگائے ہیں۔ مودی جی کے گجرات پر ان کی بڑی نظر کرم رہی اور انہوں نے وہاں سب سے زیادہ 623 ٹاورس لگوائے، لیکن اتر پردیش جہاں کہ آبادی سب سے زیادہ ہے، جہاں کا شیئرفل سب سے زیادہ ہے، جہاں غریبی سب سے زیادہ ہے اور دیہاتی علاقےزیادہ ہیں، وہاں پر 486 ٹاورس لگائے ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ گجرات کو اتنا پرفرینس دینے اور یوپی کو پیچھے رکھنے کا کیا کارن ہے؟

ڈا॰ شکیل احمد: सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य गुजरात का अपमान न करें। गुजरात किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, गुजरात गुजरात की जनता का है और इस देश का अंग है...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: यू॰पी॰ सब का नहीं है?...(व्यवधान)...

†**شری شاہد صدیقی : یوپی سب کا نہیں ہے؟** مداخلت

†Transliteration of Urdu Script.

डा॰ शकील अहमद: दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा क्राइटेरिया है कि जहां से जैसे डिमांड आती है, वहां उस हिसाब से हम कार्यवाही करते हैं। इस बारे में बहुत स्पष्ट नीति है और किसी व्यक्ति का नाम लेकर किसी राज्य को अपमानित करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

SHRIMATI S.G. INDIRA: In the reply of the Minister, it has been mentioned that mobile services of BSNL wherever deployed in rural areas in the country are working satisfactorily, in general. But we are not satisfied. Sir, growth of mobile connections in rural areas as compared to urban areas is very less. In order to get the line clear, TRAI has held a meeting and recommended that all service providers, that is, BSNL, Airtel, Reliance, etc., should put up towers. TRAI has also recommended in this regard that the Government can also give subsidy. What is the response of the Government to help the rural and urban areas?

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, TRAI has recommended sharing of the infrastructure. TRAI has two roles in it. One is advisory role. The Government is free to accept the advice or reject it. The second role of TRAI is of a regulatory regarding fixation of tariff and other things. TRAI has recommended to enhance the teledensity through the USO Fund in rural areas. That is why we are planning to have 7,871 towers covering 2,12,304 villages at a cost of Rs. 587.88 crores.

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, I have two parts of my supplementary. First, I can see that in the year 2006-07, in West Bengal and North East except Assam, the number of GSM towers has decreased and the number of WLL has increased in these two areas. What are its causes? I would like to know this from the hon. Minister. Secondly, I come from a remote areas, Cooch Behar. In remote areas and border areas, the BSNL is not providing...

MR. CHAIRMAN: Please come to your question.

SHRI TARINI KANTA ROY: BSNL is not providing fixed line generally...

MR. CHAIRMAN: Please come to your supplementary.

SHRI TARINI KANTA ROY: Yes, Sir. WLL line is also not provided there. And, when we look at mobile telephony in rural areas of the country, the mobile services there are not satisfactory...

MR. CHAIRMAN: Your supplementary is over. Now, the hon. Minister to reply.

SHRI TARINI KANTA ROY: I would like to know what steps are being taken by the Government to develop the system.

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, we provide WLL connection where there is problem in laying cables in difficult terrains, like, the hilly areas. Also, where the number of inhabitants is less, we provide WLL. As far as border area is concerned, previously, there was a rule that within 10 kms. of the international border, we should not install mobile towers. Now, very recently, the Home Ministry has given us permission to install towers with some conditions. So, in those areas, we will look into the possibility and implement it as soon as we can.

प्रो॰ राम देव भंडारी: मान्यवर, यह सही है कि माननीय मंत्री जी टेलिफोन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। मगर इन्हें और भी प्रयास करने हैं। महोदय, मैं बिहार से आता हूं, उत्तरी बिहार से। वहां के लगभग 20 जिले बाढ़-पीड़ित हैं। उन जिलों में कुछ ऐरियाज ऐसे भी हैं, जहां लगभग आधा वर्ष पानी भरा रहता है। वहां केबल बिछाना बहुत मुश्किल है। वहां WLL सेवाएं दी जाती हैं, मगर वहां WLL सेवाएं बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने कई कारण बताएं हैं कि बिजली नहीं रहती है, केबल काट लिए जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में, जहां केबल बिछाना मुश्किल है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है और जिस जेनरेटर की बात यह कर रहे हैं, वे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। हो गया। ...(व्यवधान)... आप क्वैश्चन कर लीजिए ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: कई जगह से शिकायतें आती हैं कि उनको समय पर डीजल नहीं मिलता है। क्या उन्होंने इसका सर्वेक्षण कराया है कि कितने घंटे बिजली नहीं मिलने से टेलिफोन टावर्स काम नहीं करते हैं, कितने घंटे डीजल नहीं मिलने से टेलिफोन टावर्स काम नहीं करते हैं, यानि कुल मिलाकर टेलिफोन टावर्स सही रूप से कितने घंटे काम करते हैं, क्या इसका सर्वेक्षण कराया है? सर्वेक्षण कराने से इनको यह पता लग जाएगा ...(व्यवधान)... कि किस कारण से ये टावर्स काम नहीं करते हैं?

श्री सभापति: ठीक है। आप बोलिए।

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि ये टावर्स सामान्यत: काम कर रहे हैं। बिजली की कमी की वजह से कभी-कभी व्यवधान होता है तो हमारे जेनरेटर्स उसको पूरा

करने की कोशिश करते हैं। कहीं-कहीं जेनरेटर्स के भी लगातार चलने की वजह से, जो कि एक टेक्निकल चीज है, कहीं अगर जेनरेटर खराब हो गया, तो कुछ व्यवस्था होती है, उसमें भी हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य ने जो मोबाइल और केबल की बात की, निश्चित रूप से केबल बिछाने में वहां मुश्किल है। मैं भी उसी जिले से आता हूं, जहां से माननीय सदस्य आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो वायरलेस है, यह आजकल के च्वायस की टेक्नोलॉजी है। हम कम-से-कम अभी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहते हैं कि उनके जिले में अभी हम लोग मोबाइल के लगभग 40 से अधिक नये टावर्स दो महीने के अंदर ...(व्यवधान).... इन्हीं सब कमियों की वजह से ...(व्यवधान)....

प्रो॰ राम देव भंडारी: आपको वहां कुछ उद्घाटन भी करना है। जाकर उद्घाटन कर दीजिए .. .(व्यवधान)....

डा॰ शकील अहमद: माननीय सदस्य का जो इलाका है, उसमें हम लोग निश्चित रूप से उद्घाटन भी करेंगे। वहां अभी 40 से ज्यादा मोबाइल के टावर्स लगाने हैं।

*602. [*The Questioner (Shri Sanjay Raut) was absent. For answer vide page* 40]

MoU with States for capacity building programme for PRIS

*603. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

(a) whether the Central Government has signed an MoU with the States to launch an effective capacity building programme for Panchayati Raj Institutions (PRIs) which in turn would promote and implement the drinking water schemes;

(b) if so, the schemes that are to be implemented by PRIs and how much financial outlay is earmarked for the same in the year 2007-08;

(c) whether the PRIs would be entrusted with the task of subsequent operation and maintenance of the scheme;

(d) if so, how much additional work force would be roped in; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.